16 जून2015

# दक्षिण चीन सागर में चीन का भूमिपुनर्ग्रहण:क्षेत्र के लिए निहितार्थ

डॉ.राहुल मिश्रा

हाल ही में दक्षिण चीन सागर में भूमि पुनर्ग्रहण पर होने वाले वि वादों के बीच, चीन ने मई 2015 में अपना सैन्य रणनीति श्वेत पत्र जारी किया।चीन और वियतनाम समुद्र में भूमि पुनर्ग्रहण और विरोधी भूमि पुनर्ग्रहण में शामिल रहे हैं , जबकि अमेरिका विवादित समुद्र में नौवहन की अधिक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है।पेंटागन द्वारा 8 मई, 2015 को जारी की गई एक रिपोर्ट ने भी पुष्टि की है कि चीन ने बड़े पैमाने पर भूमि पुनर्ग्रहण की शुरुआत की है।चीन के मुखर रवैयेको उन रिपोर्टों द्वारा प्रदर्शित किया गया है जिनमें इसने कथित तौर पर एक पुनर्गृहीत द्वीप पर मोबाइल तोपखानाअस्त्र तैनात किए हैं।जबकि वियतनाम की मुखर प्रतिक्रिया और विवादित समुद्र के बारे में अमेरिकी सार्वजनिक घोषणा चीन के हितों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है , बीजिंग दक्षिण चीन सागर पर अपनी मुखर मुद्रा में आगे बढ़ रहा है , यह एक ऐसा विकास जो क्षेत्रीय शांति और सद्भाव के हित में नहीं है।चीनी श्वेत पत्र के अनुसार:

> *चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों और हितों से संबंधित मुद्दों पर, इसके कुछ अपतटीय पड़ोसी उत्तेजक कार्रवाई करते हैं और चीन की चट्टानों और द्वीपों पर अपनी सैन्य उपस्थिति को सुदृढ़ करते हैं , जिस पर उनका अवैध कब्जा है।कुछ बाहरी देश भी दक्षिण चीन सागर के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं; कुछ ने चीन के खिलाफ निरंतर हवा और समुद्र में निगरानी और टोह बनाए रखा है।इस प्रकार यह चीन के लिए अपने समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक दीर्घकाल से लंबित कार्य है।*

चीन दक्षिण चीन सागर में चट्टानों, टापुओं, प्रवालद्वीपों, रेत के ढूहों, किनारों और द्वीप समूहों पर संप्रभुता का दावा करता है।इस विवाद में ब्रुनेई, चीन, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम जैसे छह सरकारों द्वारा क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों के अतिव्यापी दावे शामिल हैं।चीन वस्तुतः नौ -रिक्तस्थान युक्त लाइनों के स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है , जिसे मई 2009 में महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीएलसीएस) को प्रस्तुत किया गया था।

**चीन के कृत्रिम द्वीप**

पिछले कुछ महीनों में , चीन केदक्षिण चीन सागर में भूमि पुनर्ग्रहण के प्रयासों और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में शामिल होने की खबरें आई हैं।अब तक , चीन ने कम से कम 2,000 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया है और कथित तौर पर बंदरगाहों, ईंधन भंडारण डिपो, हवाई पट्टियों और रडार साइटों के रूप में बुनियादी ढांचे का विकास किया है।माना जाता है कि कृत्रिम द्वीपों का, चीन द्वारा सैन्य चौकी के रूप में इस्तेमाल कि या जाएगा।इस निर्माण का वियतनामी और फिलिपिन पक्षों द्वारामजबूत विरोध किया गया है, लेकिन चीन ने अपने उत्तर में अपनी गतिविधियों को "चीन की संप्रभुता के दायरे में" आने और समुद्र में नौ वहन सुरक्षा में सुधार करने का एक उपाय बताया है।चीन ऐसी गतिविधियों को किसी भी देश के प्रति निर्देशित न होने और केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए की जाने के रूप में भी चित्रित करता है।

फिर भी, ये द्वीप केवल द्वीपों पर अपने दावों को मजबूत करने में ही चीन की मदद नहीं करेंगे, बल्कि उसके सशस्त्र बलों के संचालन क्षेत्र में भी विस्तार करेंगे। इसके अलावा , यह चीन को सी -लाइन ऑफ़ कम्युनिकेशन (एसएलओसी) की निगरानी और सुरक्षा के लिए एक मु क्तअवसर प्रदान करेगा। सागर में केवल वह मुख्य एसएलओसी ही शामिल नहीं है जो दक्षिण पूर्व एशिया को पूर्वोत्तर एशिया के साथ चीन के कच्चे तेल के आयात के लगभग 80 प्रतिशत से जोड़ता है, बल्कि यह मछली पकड़ने के बड़े क्षेत्र को भी आवृत करता है और यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है।

हालाँकि, ये घटनाक्रम वियतनाम और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण हैं क्योंकि वियतनाम ने स्प्राटली द्वीप समूह में वियतनाम-नियंत्रित सैंड के और पश्चिम लंदन रीफ पर भूमि को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया है। 14 मई को, वियतनाम ने पहली बार स्वीकार किया कि उसने कुछ निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया है लेकिन इसे "सामान्य और वैध " कहा है। चीन के कदम को विस्तारवादी रूप में देखा गया है , जबकि वियतनाम इसे एक संभावित आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा के लिए अपने ही क्षेत्र में किए गए प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में संदर्भित करता है।दिलचस्प बात यह है कि वियतनामी ठिकानों के पास के क्षेत्रों में चीन कीनवीनतम भूमि सुधार गतिविधियां की जाती हैं।

**दक्षिण चीन सागर में अमेरिका-चीन पंक्ति**

काफी समय से, अमेरिका दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर दृढ़ और खुला है।व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव , जोश अर्नस्ट के प्रेस बयान में यह उल्लेख कियेजानेके साथ कि "दक्षिण चीन सागर में स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हित के लिए महत्वपूर्ण है ", अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है।चीन , जो एशिया नीति के लिए अमेरिकी धुरी को चुनौती देता रहा है, दक्षिण चीन सागर विवाद में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध करता है।इस मुद्दे पर ताजा तनाव अमेरिका और वियतनाम को एक-दूसरे के करीब आने के अवसर दे रहा है।इस संदर्भ में अमेरिकी रक्षा सचिव एश्टन कार्टर की हालिया यात्रा को भी देखा जाना चाहिए। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की मुखरता का मुकाबला करने के लिए , अमेरिका वियतनाम और इस क्षेत्र के अन्य देशों की अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने मेंमदद कर रहा है। हाल ही के एक कदम में , अमेरिका ने वियतनाम को अमेरिकाकी मेटल शार्क गश्ती नाव खरीदने में मदद करने के लिए 18 मिलियन अमरीकी डॉलर देने का वादा किया है।इसके अलावा, अमेरिकी रक्षा सचिव, एश्टन कार्टर, ने 30 मई, 2015 को सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला संवाद में 'दक्षिण-पूर्व एशिया समुद्री सुरक्षा पहल 'की स्थापना का प्रस्ताव रखा।प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को दक्षिण चीन सागर में निहित करना और वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को सैन्य रूप से तैयार करना है, जो निवारक के रूप में कार्य करेंगे और यथास्थिति बनाए रखेंगे।

**क्या दक्षिण चीन सागर का विवाद अगलाप्रज्ज्वलन बिंदु है?**

जाहिर है, सैन्य रणनीति श्वेत पत्र में उल्लेख और दक्षिण चीन सागर में नवीनतम कदमों के साथ, चीन अपनी मुखर मुद्रा का प्रदर्शन कर रहा है।चीन पहले से ही समुद्र के ऊपर एक वायु रक्षा पहचान क्षेत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है।इन विकासों के साथ, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ चीन के संबंध दांव पर होंगे।

अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर समय-समय पर बयान जारी किए हैं, परचीन के अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर इसका अल्पकालिक प्रभाव है।हालांकि , अमेरिका के इस तरह के बयानों पर बयानबाजी की गई है क्योंकि चीन पर राजनयिक और सैन्य दबाव डालने के लिए अमेरिका द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है।

अभी भी काफी कुछ देखना बाकी है, पहली बात, क्या अमेरिका दक्षिण चीन सागर में बड़ी जिम्मेदारी संभालने के साथ एशिया की अपनी धुरी को एक नया अर्थ देने के लिए तैयार है ; दूसरी बात, दक्षिण चीन सागर विवाद के समाधान पर क्षेत्रीय सहयोगियों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने के अमेरिका के प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ेगा।

दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखर मुद्राओं का प्रभाव दो गुना होने की संभावना है:

- इससे न केवल चीन की अच्छी पड़ोसी नीति को और नुकसान होगा , बल्कि इंडोनेशिया सहित इस क्षेत्र में कई हितधारकों की आशंकाओं को भी बल मिलेगा, जो विवाद में प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है, लेकिन चीन की नाइन डैश लाइन से आशंकित है जो इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अतिक्रमण है , भूमि के पुनर्ग्रहण की गतिविधियां पहले से ही अविश्वास को बढ़ा रही हैं।आखिरकार , यह चीन की वन बेल्ट , वन रोड पहल , मुख्य रूप से इसके समुद्री चरण, मैरीटाइम सिल्क रोड (एमएसआर) को साकार करने में एक बाधा साबित होगा; तथा

- दूसरे, अमेरिका ने पहले ही वियतनाम और फिलीपींस की सैन्य क्षमताओं को विकसित करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है , अमेरिका-जापान संबंधों के मामले में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी जाती है।हालाँकि अमेरिका अभी भी वियतनाम के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में एक सैन्य आयाम जोड़ने में धीमा हैऔर रक्षा सहयोग अभी तक सैन्य रूप से मजबूत वियतनाम बनाने और दक्षिण चीन सागर के विवाद में अमेरिका-वियतनाम के गठबंधन को प्राप्त करने की अपनी पूरी क्षमता प्राप्त नहीं की है परयह निश्चित रूप से चीन के हित में नहीं है।

हालांकि निकट भविष्य में कोई सैन्य टकराव नहीं होगा, पर तनाव का स्तर निश्चित रूप से बढ़ गया है।संघर्ष में शामिल देशों के साथ दक्षिण चीन सागर और अमेरिका का उल्लेख यह दर्शाता है कि चीन का दृष्टिकोण असंबद्ध और अस्वीकार्य रहेगा।दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम की भूमि पुनर्ग्रहण की गतिविधियों ने चीन के तेजी से बढ़ते रवैये के बारे में अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच खतरे की घंटी बजाने की क्षमता है, जिसने स्थिति को गंभीर रूप से तनावग्रस्त कर दिया है।संक्षेप में , इस क्षेत्र के लिए दक्षिण चीन सागर विवाद का 'रचनात्मक' समाधान तलाश करना अनिवार्य है , जो अमेरिका द्वारा पर्याप्त रुचिदिखाने में कमी और चीन की तुलना में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की बहुत कम सैन्य क्षमताओं अपने वर्तमान स्वरूप में दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता की घोषणा के साथ बंद होता प्रतीत नहीं होता है।

*****

*डॉ.राहुल मिश्रा, भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।